भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2980
बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

2980. श्री सी. एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्री नवसकनी के:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु के विशेष संदर्भ में देश में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, प्रोत्साहनों अथवा राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से तमिलनाडु में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों- सौर, पवन, बायोमास और लघु डेल संयंत्र की संख्या और क्षमता (मेगावाट में) कितनी है;

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार तमिलनाडु में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा में वृद्धि करने अथवा नई योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और ऑफ-ग्रिड समाधानों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत, तमिलनाडु तथा देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदान की जा रही केंद्रीय वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में, निजी क्षेत्र के डेवलपरों द्वारा अधिकतर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। तथापि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें देश में

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास को बढ़ावा देने तथा स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान शामिल हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के पांच वर्षों के दौरान, 6192.02 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजनाएं, 2435.57 मेगावाट की पवन विद्युत परियोजनाएं, तथा 24.93 मेगावाट की जैव विद्युत परियोजनाएं तमिलनाडु राज्य में चालू की गई हैं।

(ग) तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के लिए ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ङ.) एमएनआरई, तमिलनाडु राज्य सहित देश के सभी क्षेत्रों में पीएम कुसुम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों को स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण तथा उनकी बंजर/परती/कृषि भूमि में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिसे तमिलनाडु राज्य सहित देश के सभी क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत, घरों द्वारा स्थापित रूफटॉप सौर स्थापनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

'नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2980 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

<u>पिछले पांच वर्षों के दौरान चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता का विवरण</u>

क. <u>सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</u>

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सौर पार्क	सीपीएसयू	रूफटॉप सोलर	पीएम-कुसुम	अपशिष्ट से ऊर्जा	जीईसी	बायोमास	बायोगैस
2020-21	68.18	620.25	324.20	156.44	7.57	159.52	6.22	30.04
2021-22	207.33	27.37	1460.20	389.30	75.04	134.67	14.48	7.23
2022-23	676.11	35.50	1532.60	801.37	57.60	250.00	4.91	10.28
2023-24	715.50	1081.14	1498.60	992.36	20.82	334.99	4.18	45.54
2024-25	373.84	557.67	7777.61	2563.93	86.17	357.69	15.99	44.79

ख. <u>तमिलनाडु</u>

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पीएम-कुसुम	सीपीएसयू योजना	रूफटॉप सोलर	ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर	बायोमास	बायोगैस	अपशिष्ट से ऊर्जा
2020-21		80.50	4.4			2.56	
2021-22	20.30			59.26	0.02		
2022-23			20.54	87.81	1.03	0.34	
2023-24	2.59	80.97	13.94			0.47	2.36
2024-25	6.48	1.76	172.64	10.47		4.95	15.18

*****